

“हरियालो राजस्थान” अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा हुआ : मुख्यमंत्री

राजस्थान को हरा-भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : भजनलाल शर्मा

जयपुर । ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत प्रदेश में 1० करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान के तहत पोस्टर विमोचन किया तथा वन मंत्री ने मुख्यमंत्री को पौधा भी भेंट किया।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर, हमारी सरकार ने राजस्थान को हरा-भरा बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने पिछले साल हरियाली तीज के पर्व पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत ‘हरियालो राजस्थान’ का शुभारंभ किया था।

हमारा लक्ष्य है कि पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जाए। इस अभियान के तहत पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से वन मंत्री संजय शर्मा ने मुलाकात कर हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर बधाई दी।

सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गत वर्ष हमारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर हमने 7 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए थे। उन्होंने कहा कि इस साल भी हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य

को पार कर लिया है तथा अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा काल अभी चल रहा है, ऐसे में विभाग इस अभियान के तहत लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें।

शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धिप्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता

को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

पौधरोपण सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हरित भविष्य देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आमजन से ज्यादा पौधे लगाने लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत अब तक 37 लाख 51 हजार पौधे व्यक्तिगत स्तर पर तथा 9 करोड़ 83 लाख पौधे ब्नोंक स्तर पर लगाए गए हैं। करीब 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। साथ ही, 2 लाख 74 हजार 920 पौधारोपण साइट्स पर 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा 3 करोड़ 25 लाख, ग्रामीण विकास द्वारा 2 करोड़ 65 लाख, वन विभाग द्वारा 2 करोड़, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 लाख सहित विभिन्न विभागों द्वारा पौधारोपण किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को दी मंजूरी

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश-प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण से प्रदेश में ना केवल पर्यटन को गति मिलेगी अपितु शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति भी मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1 हजार 507 करोड़ की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवा अड्डा विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआ) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस ग्रीनफील्ड हवा अड्डे में यात्रियों की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी। परियोजना के अनुसार यहां ए–321 श्रेणी के विमानों का संचालन किया जाएगा।वहीं, 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों (पीएचपी) को संचालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता बीस लाख (दसपीपीए) होगी।

फाउंटेन स्क्वायर पार्क : राजस्थान में पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला का अनूठा संगम

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है तथा यह क्षेत्र विकास के नए शिखर छू रहा है। प्रदेश में शहरी विकास आधुनिक सौंदर्यशास्त्र,

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी विकास छू रहा नए आयाम**

■ **इस पार्क में आधुनिक सुविधाओं युक्त प्रदर्शनी ग्राउंड और एम्फीथियेटर हैं, जो कि सस्टेनेबल विकास का एक मॉडल हैं।**



दो एम्फीथियेटर भी हैं। 40 करोड़ की लागत से निर्मित यह परियोजना न केवल एक कलात्मक कृति है, बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे में एक बेंचमार्क है।

इस परियोजना के केंद्र में सेंट्रल म्यूजिकल फाउंटेन है, जहां हर शाम 7 से 8 बजे तक संगीत और रोशनी के साथ पानी की स्क्रीन पर लेजर शो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनता है। इसके साथ ही, यह मंत्रमुग्ध करने वाली 3डी इमेजरी में राजस्थानी संस्कृति की कहानियांभी सुनाता है।यह फाउंटेन चार सफेद संगमरमर की शेर की मूर्तियों से घिरा हुआ है, जो शक्ति और गौरव का प्रतीक है। शौलपुर पत्थर की बनी हुई कलात्मक छतरियां और बारीकी से डिजाइन किये गए मेहराब इस स्थान को शाही एहसास देते हैं। एक ऊंचे मंच के ऊपर एक छोटा अंग्रेजी फाउंटेन यूरोपीय शैली की झलक दिखाता है, जो परंपरा और आधुनिकता का एक सहज मिश्रण है।

फाउंटेन स्क्वायर के बगल में प्रदर्शनी ग्राउंड है, जो 9 हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें एक भव्य मंच, हरित स्थान, 550 लोगों के बैठने की जगह, रिसेशन, कार्यालय स्थान,

लॉकर और शौचालय निर्मित हैं। साथ ही, कलाकारों के लिए सुविधायुक्त ग्रीन रूम भी बनाया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सोच-समझकर वास्तुशिल्प पर काम किया गया है।यहां दो एम्फीथिएटर भी बनाये गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 500 आर्गंतुकों के बैठने को व्यवस्था है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय, फ़ूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पर्याप्त पार्किंग और सुंदर टिकट खिड़कियां सभी आयु समूहों के लिए सुविधा और आराम सुनिश्चित करती हैं।

दीर्घकालिक विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के अनुरूप यहां एक समर्पित 2.0 एनएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। इस सुविधा से उपचारित ग्रे पानी का उपयोग फाउंटेन स्क्वायर और निकट स्थित सिटी पार्क की सिंचाई के लिए किया जा रहा है।फाउंटेन स्क्वायर और प्रदर्शनी ग्राउंड बेहतरीन ईजीनियरिंग का खूबसूरत उदाहरण हैं। दोनों के संरचनात्मक डिजाइन आधुनिक भूकंपरोधी और अग्निशमन प्रणालियों से लैस हैं।

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने देश विदेश में 2 4 लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया

जयपुर। विश्व प्रसिद्ध कृत्रिम अंग जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) ने अब तक देश-विदेश में 24 लाख से अधिक विकलांगों का पुनर्वास किया है। वर्ष 1975 में डी.आर. मेहता, संस्थापक और मुख्य संरक्षक द्वारा स्थापित यह संस्था इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रही है और वर्तमान में बी.एम.वी.एस.एस. के विकलांगों के पुनर्वास की विश्वभर में सबसे अग्रणी संस्था बन गई है।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डॉ. आर. मेहता ने प्रबन्ध समिति की बैठक में कहा कि वर्ष अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 तक एक लाख 78 हजार 180 विकलांगों को कृत्रिम पैर, कैलीपर्स, ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखियां, स्टिक, वाकर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।

डी.आर. मेहता ने बताया कि कुल लाभार्थियों में 48,527 विदेशी दिव्यांगों हैं, जिन्हें विदेशों में आयोजित शिविरों के माध्यम से निःशुल्क कृत्रिम पैर और उपकरण उपलब्ध कराए गए।

जयपुर फुट की निर्माता संस्था बी.एम.वी.एस.एस. द्वारा अप्रैल 2024 से इस वर्ष मार्च तक विभिन्न स्थानों पर 82 शिविरों का आयोजन कर 31 हजार 694 दिव्यांगों का पुनर्वास



भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की प्रबंध समिति की बैठक हुई।

किया गया। बी.एम.वी.एस.एस. की देशभर में फैली विभिन्न 32 शाखाओं के माध्यम से 150 शिविरों का आयोजन कर कृत्रिम पैर और उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और निजी संस्थाओं द्वारा अब तक 46 देशों में 116 शिविरों की विदेशों में आयोजन किया। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत सरकार और निजी कम्पनियों के सहयोग से अफगानिस्तान में 75 कृत्रिम पैर और मोजम्बिक में 1230 कृत्रिम पैर लगाए गए और अन्य उपकरण निःशुल्क बांटे गए।

बी.एम.वी.एस.एस.के अध्यक्ष सतीश मेहता ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में तंजानिया, निकारगुआ, जिनिदाद और टोंगेगो, गुवाटेमोला, सूडान एवं

म्यानमार में विशेष शिविर आयोजित करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार गुयाना, गिनी एवं तंजानिया में निजी कम्पनियों के सहयोग से शिविरों के विदेशों में आयोजन होंगे।

बीएमवीएसएसने अमृतसर पंजाब में गुरुरामदेव मेडिकल कॉलेज और भोपाल में एम्स में नई शाखाएं खोली हैं। सतीश मेहता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, मेघालय में शिलांग बाडमेर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और जम्मू-कश्मीर में एम्स जम्मू में नई शाखाएं खोलने के प्रस्ताव पर कार्य हो रहा है।

समिति के सचिव डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने बताया कि समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्य और प्रमुख चिकित्सक डॉ. शिव सरीन का जयपुर में दिव्यांगों का

■ **समिति ने वर्ष अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 तक एक लाख 78 हजार 180 विकलांगों को कृत्रिम पैर, कैलीपर्स, ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखियां, स्टिक, वाकर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं।**

विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। इसके लिए मणीपाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. संदीप संचेती को लखनऊ स्थित शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

सचिव भूपेन्द्र राज मेहता ने बताया कि कुछ रोगियों के लिए अमेर में एक आश्रम चलाया जा रहा है।

समिति ने अपने ख़ोत से 45 दिव्यांगों के परिवार के लिए घर बनाने का कार्य किया है। इसी प्रकार जोधपुर के चौखाना में 120 आश्रम और बेघर महिलाओं के लिए आश्रम का निर्माण किया गया है। जहां पर 100 आवासी रह रहे हैं।

मार्च में शुरू होगा कार्डियक टॉवर, आयुष्मान टॉवर में होंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं : खींवसर

हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर होगा विशेष फोकस : चिकित्सा मंत्री

जयपुर । प्रदेशवासियों को आगामी समय में विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। इसके लिए सर्वाई मानसिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आयुष्मान टॉवर के काम को गति दी जाएगी और हाई एण्ड सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसी प्रकार कार्डियक टॉवर का काम जल्द पूरा करते हुए इसे 30 मार्च से शुरू किया जाएगा। साथ ही, सर्वाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन इकाई का विस्तार करते हुए इसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हर माह समीक्षा बैठक होगी।

मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगवालर को सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आयुष्मान टॉवर, कार्डियक टॉवर एवं आपातकालीन इकाई के विस्तार कार्यों की गहन समीक्षा की और इन सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए, लेकिन गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं हो। हमारा लक्ष्य इन सुविधाओं को सिर्फ जल्द शुरू करना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के लोगों को इनका पूरा लाभ



चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगवालर को सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की बैठक ली।

मिले और इनका निर्माण हाई एण्ड टेक्नोलॉजी और सभी सुविधाओं के साथ हो।

खींवसर ने कहा कि आयुष्मान टॉवर की प्लािंग में रही खामियों को चिन्हित करने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन किया है। अधिकारी यह ध्यान रखें कि इसके कार्य में किसी तरह की कमी नहीं रहे। इसको विश्वस्तरीय रूप देने के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों की राय एवं सेवाएं लें। इस भवन में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बनाए रखने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन पर विशेष रूप से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किसी भी स्तर पर कोई बाधा या वित्तीय समस्याएं हों और तुरंत अवगत कराएं।

चिकित्सा मंत्री ने कार्डियक टावर के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसके भवन का कार्य पूरा करने के साथ ही उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन का काम भी जल्द पूरा करें। यह सुनिश्चित करें कि 30 मार्च, 2026 से इसे प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने सर्वाई मानसिंह अस्पताल में चल रहे आपातकालीन इकाई के विस्तार कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान इमरजेंसी इकाई अस्पताल में आने वाले मरीज भार को देखते हुए काफी छोटी है। इसका विस्तार करने के साथ ही इसे अत्याधुनिक एवं रोगियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष

कुमार ने बताया कि आयुष्मान टॉवर को विश्व स्तरीय रूप देने के लिए इसमें उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निरंतर विचार-विमर्श चल रहा है। साथ ही, इसका प्रबंधन भी बेहतरीन हो, इसके लिए विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है, ताकि इसका संचालन प्रारंभ होने के बाद किसी तरह की समस्याएं नहीं आए। उन्होंने कार्डियक टॉवर एवं आपातकालीन इकाई की प्रगति से भी अवगत कराया।

इस अवसर पर सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक मोहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा मुकेश कुमार, उप निदेशक डॉ. वंदना शर्मा, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया

जयपुर। जयपुर सिल्वर एसोसिएशन की ओर से पारिवारिक स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माधोगड, सीकर रोड राजावास में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान कपल गेम, विल्डून गेम, स्विमिंग, क्रिकेट, तंबोला हाउसी और लाइव बैंड सभी गतिविधियां हुईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल अग्रवाल (डेरवाला) ने बताया कि यह आयोजन पारिवारिक मेजबानी और आपसी सहयोग को मजबूत करने के

एल.आई.सी. की लैप्स पॉलिसियां पुनर्जीवित हो सकेंगी

जयपुर (कासं)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने अपनी लैप्स पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए आकर्षक प्रस्ताव पेश किया है। व्यक्तिगत लैप्स पॉलिसियों के लिए 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार के लिए पात्र होने पर सभी गैर लिंकड बीमा योजनाओं के लिए विलंब शुल्क में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जो कि अधिकतम 5 हजार रुपये तक होगी। इस अभियान के तहत पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने

■ **18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक चलाया जायेगा विशेष पुनरुद्धार शिविर**

के अधीन, प्रथम अवैतनिक प्रीमियम की तिथि से 5 वर्षों के भीतर की पॉलिसियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो पॉलिसियां प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान समाप्त हो गई हैं तथा जिनकी पॉलिसी अवधि पूरी नहीं हुई है, वे इस अभियान में पुनर्जीवित होने की पात्र होंगी।

ग्रेटर निगम ने चार जोन उपायुक्तों के कार्यक्षेत्र बदले

जयपुर (कासं)। ग्रेटर नगर निगम प्रशासन ने चार उपायुक्त, एक सहायक अभियंता और तीन कनिष्ठ अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए।

आदेश के मुताबिक उपायुक्त करणी सिंह को विद्याधर नगर जोन, मनोज कुमार वर्मा को राजवन्ध प्रथम और आयोजना प्रथम, अपर्णा शर्मा को गैराज शाखा, अशोक कुमार शर्मा को मुरलीपुरा जोन उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सहायक अभियंता मनोी कुमारवत को विद्याधर नगर जोन भेजा गया है।

क्या सीतापुरा में आई.ओ.सी.एल. गैस प्लांट के पास सघन आबादी नहीं है?

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस गैस प्लांट के दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक इलाके में स्थित आई.ओ.सी.एल. के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के आसपास मौजूद सघन आबादी बसावट होने के बारे में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

आई.ओ.सी.एल. के इस गैस प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि, क्या इस औद्योगिक क्षेत्र में जेडीए और नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियां विकसित की हैं। इस गैस प्लांट के आसपास जितनी भी आबासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक व अन्य इकाईयां संचालित हैं, उनका पूरा विवरण अदालत में पेश किया जाये। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश औपप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए।

हाईकोर्ट ने रीको प्रशासन से यह बताने को कहा है कि, औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे अस्थायी प्रतिष्ठान या उद्योग संचालित हैं, जो खतरनाक गतिविधियों के दायरे में आते हैं। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालना में आईओसीएल की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी का इस

■ **अदालत ने मुख्य सचिव और रीको प्रशासन से, सीतापुरा में संचालित खतरनाक श्रेणी के उद्योग और इनसे सटी आवासीय कॉलोनियाँ, शैक्षणिक व अन्य इकाईयों का पूरा विवरण मांगा है।**

■ **याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में 7 दिन तक लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए।**

■ **इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है। इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी काँसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं। इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए।**

■ **इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है। इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी काँसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं। इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी काँसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं। इसके शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं।**

गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए। इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है। इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी काँसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं। इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए।

इस पर न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायित्व करने को कहा है। जिसमें न्यायालय को जरिये शपथ पत्र यह सूचित किया जाए कि क्या सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और उसके आसपास में राज्य द्वारा जेडीए और नगर निगम जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से आवासीय कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं अथवा नहीं।

अदालत ने अपने आदेश में रीको से यह भी कहा है कि वह भवनों के निर्माण के साथ-साथ, खतरनाक भवनों या खतरनाक उद्योगों के निर्माण के लिए रीको द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदंडों को भी रिकॉर्ड पर पेश करें, ताकि न्यायालय इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके।